मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.11.2014 को योजना भवन, लखनऊ स्थित कक्ष संख्या–111 में फिफ्थ इस्टेट के सामाजिक उद्यमिता सम्मेलन से सम्बन्धित बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सूची संलग्न है।

- श्री वेंकिटेश रामकृष्णन, मुख्य अधिवक्ता एवं सलाहकार, फिफ्थ इस्टेट द्वारा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, प्रमुख सचिव नियोजन और अन्य विभाग के उच्चाधिकारियों सहित वहॉ उपस्थित फिफ्थ इस्टेट के सहभागियों का स्वागत किया गया। श्रीमती पल्लवी गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक फिफ्थ इस्टेट द्वारा सम्मेलन के उद्देश्य एवं विषयवस्तु के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया और राज्य के आर्थिक, तकनीकी एवं शैक्षणिक विकास में गति लाये जाने हेतु नवीनतम तकनीक पर आधारित योजनाओं का प्रगतिशील उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से प्रस्तुतीकरण कराया गया।

  मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा बैठक में उपस्थित फिफ्थ इस्टेट के सहभागियों द्वारा प्रस्तुत योजना के बारे में अन्य विभागों के विभागीय अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः–

परियोजना 1: आउट ऑफ स्कूल शहरी स्लम के बच्चों के लिए समाधानः ज्ञान शाला

ज्ञान शाला प्रतिनिधि द्वारा दो प्रस्तावों पर प्रस्तुतीकरण किया गया। (1) उत्तर प्रदेश के शहरों में स्कूलों से ड्राप आउट के फलस्वरूप निकाले गये गरीब वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा तथा (2) सरकारी स्कूलों के गरीब तबके के बच्चों के शैक्षिक प्रर्दशन में प्राइमरी एवं माध्यमिक स्तर पर सुधार। विचार–विमर्श में यह ज्ञात हुआ कि यह सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू है और कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान प्रस्ताव में कोई वित्तीय उपाशय राज्य सरकार के स्तर पर निहित नही है। यह स्पष्ट किया गया कि फिलहाल वर्तमान में संचालित आउट आफ स्कूल केन्द्र को विभाग अनुश्रवण करें व उसे अपनी शिक्षा प्राणली से इन्टीग्रेट करें व इस प्रयोग के अनुभव के आधार पर भविष्य की रणनीति तय हो।

- मुख्य सचिव द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को दो सप्ताह में ज्ञान शाला के प्रतिनिधि के साथ विचार–विमर्श कर प्रस्तावों पर मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैण्डिंग (MOU) पर सहमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के निर्देश दिये।

(कार्यवाहीः प्रतिनिधि ज्ञानशाला/सचिव बेसिक शिक्षा)

परियोजना 2: कम लागत सैनिटरी नैपकिन और सफाई उत्पादः पंचायत उद्योग केन्द्र महोबा

जिलाधिकारी, महोबा द्वारा पंचायत उद्योग केन्द्र, महोबा द्वारा निर्मित कराये जा रहे कम लागत सैनिटरी नैपकिन एवं कम लागत के सफाई उत्पादों के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

मुख्य सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गये कि प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए तथा इसे अन्य जिलों में लागू करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहयोग से समुचित प्रस्ताव तैयार करेंगे। इस प्रयोग में इनसिनिरेटर (Incinerator) को भी शामिल किए जानें की आवश्यश्कता पर बल दिया गया।

(कार्यवाहीः पंचायतीराज विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग वं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग)

कम लागत सैनिटरी नैपकिन पर एक परियोजना का अपने जनपदों में लागू करने के इच्छुक जिलाधिकारियों–कानपुर, शामली, वाराणसी, गोरखपुर, महोबा, कन्नौज सहित अन्य सभी जिलाधिकारियों और प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग को परिचालित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः प्रतिनिधि पंचायत उद्योग केन्द्र, महोबा/पंचायतीराज विभाग/जिलाधिकारी कानपुर, शामली, वाराणसी, गोरखपुर, महोबा, कन्नौज/नियोजन विभाग/फिफ्थ इस्टेट)

परियोजना 3: माइक्रो कोल्ड स्टोरेज यूनिटः इकोज़ेन सोलुशंस

कृषि, उद्यान एवं फार्म उत्पादों के ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता में वृद्धि कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि संवर्द्धन हेतु इकोज़ेन सोलुशंस के प्रतिनिधि द्वारा सोलर ऊर्जा चालित 5 मीटरिक टन से अधिक क्षमता के माइक्रो कोल्ड स्टोरेज यूनिट का प्रस्तुतीकरण किया गया और इनकी कम लागत और ग्रीमाण दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इसकी उपयोगिता के दृष्टिगत विचार किया गया।

- जिलाधिकारी, कानुपर/बाराबंकी/शामली को फूल उद्योग के लिए अपने जिलों में सोलर माइक्रो कोल्ड स्टोरेज का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रस्ताव उद्यान विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भेजने पर विचार करने का निर्देश दिया गया ताकि राष्ट्रीय औधानिकरण मिशन के अन्तर्गत इनके वित्तीय पोषण की व्यवस्था हो सके।

(कार्यवाहीः जिलाधिकारी, कानपुर/बाराबंकी/शामली/ ग्राम विकास विभाग)

- जिलाधिकारी के अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में शामली में प्राग्रेसिव फार्मर्स कोआपरेटिव द्वारा जनपद के किसानों के लिए चलाये जा रहे पायलट प्रोजेक्ट साइट का

इकोज़ेन सोलुशंस की उपस्थित का एंव प्रयोग के प्रसार किए जानें के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः एकोज़ेशन सोलुशंस/जिलाधिकारी,शामली)

- उपस्थित केर्नेल देस्वाल इकोज़ेन सोलशंस से एक माइक्रो कोल्ड स्टोरेज यूनिट प्राप्त करने की कार्यवाही करेगें।

(कार्यवाहीः केर्नेल देस्वाल)

<u>परियोजना 4: शिक्षा व बेरोजगारी के अन्तर को कम करने की परियोजनाः मेधा</u>

राज्य में वरोजगारी की समस्या के निदान हेतु सरकारी आई.टी.आई./ पॉलिटेक्निक एवं डिग्री कालेजों के प्रागंण में छात्रों के कौशल विकास, काउंसलिंग और प्लेसमेंट की सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से सहभागिता केन्द्रों में 90 घंटे का कोर्स प्रायोजित करने के संबंध में मेधा के प्रतिनिधि द्वारा अपनी परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके माध्यम से सरकारी डिग्री कॉलेजों और पॉलिटेक्निक और आई.टी.आई प्रांगण में पायलट प्रोजेक्ट चलाने का प्रस्ताव किया गया।

- मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा को मेधा के पायलट परियोजना के लिए 5 पॉलिटेक्निक कालेज राज्य में निर्दिष्ट किए जानें के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः तकनीकी शिक्षा विभाग)

- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को भी मेधा के कार्यक्रम को औपचारिक रूप से "फिनिशिंग स्कूल पहल" के साथ लिंक किए जाने हेतु समुचित जानकारी कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये तथा 10 सरकारी डिग्री कॉलेजों में मेधा के पायलट प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए मेधा द्वारा प्रस्तुत MOU पर विचार करने के निर्देश दिये गये।
- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को "उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण" के तहत मेधा के कार्यक्रम को औपचारिक रूप से RUSA के साथ लिंक किए जानें हेतु आवश्यक जानकारी कर त्वरित कार्यवाही किए जानें के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाहीः उच्च शिक्षा विभाग)

- जिलाधिकारी, गोरखपुर/शामली/कन्नौज को अपने जिलों में मेधा को पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने हेतु विचार किए जानें के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी शामली द्वारा इस परियोजना को अपने जनपद के दंगा प्रभावित क्षेत्र के सरकारी कालेजों में लागू करने पर बल दिया गया और वहॉ की आपराधिक छवि की बावरिया जाति के लोगों के लिए इसका विशेष उपयोगी होना सूचित किया गया।

(कार्यवाहीः जिलाधिकारी, गोरखपुर/शामली/कन्नौज)

परियोजना 5: मोबाइल डेटा संग्रह और विश्लेषण: टाटा टेली सर्विसेज

टाटा टेलीसर्विसेज के प्रतिनिधि द्वारा डाटा एकत्रीकरण तथा विभिन्न विभागीय सर्वेक्षण कार्यो के लिए इस उपकरण की उपयोगिता के बारे में बैठक में प्रस्तुतीकरण किया गया। विचार विमर्श में यह उभर कर आया कि सरकार ने बीएसएनएल (BSNL) के साथ पहले ही 5 साल का MOU किया है और पहले से ही बीएसएनएल हैंडसेट और सिम खरीदा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने बी.एस.एन.एल. के माध्यम से सचांर व्यवस्था स्थापित कर ली है। वर्णित स्थिति में टाटा टेलीसर्विसेज के साथ पार्टनरशिप किया जाना सम्भव नहीं है, फिर भी कम्पनी द्वारा आवेदन करने पर इसे पायलेट योजना के रूप में चलाये जाने हेतु प्रयास किया जा सकता है।

- बैठक में यह निर्देश दिए गये कि टाटा टेलीसर्विसेज स्वयं जानकारी प्रदान करें कि क्या उनका सालुशन अन्य प्लेटफॉर्म तथा सर्विस प्रोवाइडर्स (प्रदाता) पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- टाटा टेलीसर्विसेज फिफ्थ इस्टेट तथा सर्वेक्षण (Survey) से संबंधित विभागों जैसे–सिंचाई, लोक निर्माण विभाग के साथ विचार विमर्श कर यह जानकारी करेगें कि क्या यह सर्विस उनके काम आ सकती है।

(कार्यवाहीः टाटा टेलीसर्विसेज फिफ्थ इस्टेट, सिंचाई/लोक निर्माण विभाग)

परियोजना 6: ई.शौचालयः

ईराम के प्रतिनिधि द्वारा ई.शौचालय पर प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि इस शौचालय का उपयोग केरल राज्य में किया जा रहा है। यह शौचालय सेंसर युक्त है जो सिक्का डालने पर आटोमेटिक कार्य करता है, यह इको फ्रेंडली, स्वच्छतापरक एवं स्वास्थ्य परक होने के कारण मितव्ययितापूर्ण है क्योंकि इसके बेसिक माडल की लागत एक लाख रूपये है। इसे उ0प्र0 की घनी आबादी के परिप्रेक्ष्य में नगरीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी मानते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा यह निर्देश दिए गये कि नगर विकास विभाग ईराम ई. शौचालय को कानपुर और लखनऊ नगर निगम से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी कानपुर के मार्गदर्शन में एक प्रस्ताव तैयार कर विचार हेतु प्रस्तुत करेंगें।

- जनपद गोरखपुर एवं शामली के जिलाधिकारी को अपने जनपदों में विशेष रूप से कलेक्टरेट परिसर में ई.शौचालय को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किए जानें पर विचार करें।
- इन इकाइयों को पर्यटन स्थलों पर लगाए जानें का सुझाव दिया गया । जिसके दृष्टिगत नगर विकास विभाग को इस संबंध में जिलाधिकारियों एवं नगर निकायों के माध्यम से उपयोग में लाने पर विचार करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः प्रतिनिधि ईराम, जिलाधिकारी, कानपुर/ गोरखपुर/शामली एवं नगर विकास विभाग)

परियोजना 7: एस एच जी (self help group) लेखांकन और एम आई एस सिस्टम (MIS) :लीप्स एंड बाउंड्स

बैठक में लीप्स एंड बाउंड्स के प्रतिनिधि द्वारा अपने एकाउंटिंग एवं टेवलेट आधारित एम आई एस सिस्टम द्वारा एस.एच.जी. और उनके जैसे अन्य समूहों का बेहतर प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, कैसे आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के गांवों के लोग प्रतिमाह मात्र रू0 35/– प्रति व्यक्ति व्यय कर उसका P.C. की भॉति उपयोग कर गांव की विभिन्न सूचना जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक आदान प्रदान कर रहे है और किस प्रकार यह उपकरण आवास एवं नगर विकास, बाल विकास, NRHM आदि योजनाओं के लिए उपयोगी हो सकता है और किस प्रकार नावार्ड में इसका उपयोग किया जा रहा है, पर विचार प्रस्तुत किये गये तथा उसके महत्व के विषय में बताया गया।

- यह निर्देश दिए गये कि लीप्स एंड बाउंड्स और नाबार्ड (NABARD) के बीच हुए MOU की एक प्रति संस्था के प्रतिनिधि द्वारा प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को यथाशीघ्र विचार हेतु उपलब्ध करायी जायेगी और प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा कुछ जिलों में इस सिस्टम को पायलट करनें के लिए अध्ययन कर तत्संबंधी प्रस्ताव परीक्षण कर उच्च निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाहीः प्रतिनिधि लीप्स एंड बाउंड्स, ग्राम्य विकास विभाग)

परियोजना 8: इकोसन शौचालयः RLS SEWA

आर.एल.एस. सेवा के प्रतिनिधि द्वारा इकोसन शौचालय पर विचार प्रस्तुत किया गया। एनबीए (NBA) के तहत मौजूदा योजना में शौचालयों के निर्माण हेतु मात्र रू0 12000/– की व्यवस्था है। अतः शेष धनराशि लाभार्थी को ही लगाना है।

- यह निर्देश दिए गये कि आर.एल.एस. सेवा शौचालय निर्माण के लिए निजी क्षेत्र से धन प्राप्त करने के पश्चात, पायलट के लिए प्रमुख सचिव, पंचायतीराज से

सम्पर्क कर सकते हैं। मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायतीराज को प्रकरण पर सम्यक रूप से विचार किए जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः प्रतिनिधि आर.एल.एस. सेवा, पंचायतीराज विभाग)

बैठक के अन्त में श्री सुधीर पवार, मा0 सदस्य, राज्य योजना आयोग और श्रीमती पल्लवी गुप्ता, निदेशक, फिफ्थ इस्टेट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तुतीकरण के बिन्दुओं की राज्य हित में उपादेयता पर अपने विचार व्यक्त किये गये। तदुपरान्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग–1
संख्याः 1789/35–1–2014–6/8(2)/2013
लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं बैठक में दिये गये निर्देशानुसार अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के स्टाफ आफिसर।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/पंचायतीराज/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/कृषि/महिला कल्याण विभाग/बाल विकास विभाग/उद्यान/चिकित्सा/ खादी ग्रामोद्योग/आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
4– जिलाधिकारी, कानपुर/लखनऊ/शामली/बाराबंकी/गोरखपुर/वाराणसी/कन्नौज/महोबा।
5– श्रीमती पल्लवी गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक, फिफ्थ इस्टेट को इस आशय से कि उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी उद्यमियों/संस्थाओं को कार्यवृत्त की प्रति अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेजनें का कष्ट करें।
6– स्टेट कोआर्डिनेटर, फिफ्थ इस्टेट/निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, लखनऊ।
7 बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागीकरण।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण एवं विभिन्न संस्थाओंके प्रतिनिधियों की सूचीः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10– प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
11– सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13– विशेष सचिव (श्री त्रिपाठी), नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
14– संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
15– निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
16– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
17– सहायक निदेशक, नगर स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
18– एम0एफ0ओ0, पी0आई0यू0, नगर स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
19– निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
20– स्टेट नोडल आफिसर, सेनिटेशन।
21– जिलाधिकारी, कन्नौज।
22– जिलाधिकारी, शामली।
23– जिलाधिकारी, महोबा।
24– जिलाधिकारी, कानपुर।
25– जिलाधिकारी, बाराबंकी।
26– जिलाधिकारी, गोरखपुर।
27– श्री विनय कुमार, मैनेजर, एस0आई0डी0वी0आई0।
28– श्री नजमुल एच0 रिजवी, ई0एन0एच0 फाउन्डेशन।
29– श्री सन्तोष द्विवेदी, प्रोग्राम कोआर्डिनेटर, वाटर–एड–इण्डिया।
30– श्री लक्ष्मन सेथुरमन, सीनियर मैनेजर, टाटा ट्रस्ट।
31– सुश्री पुर्णिमा डोरे, प्रोफेसर टाटा ट्रस्ट।
32– श्री आशीष कुमार, एच0डी0एफ0सी0।
33– श्री अर्यन सान्याल, हेड गर्वनमेन्ट रिलेसन्स, एच0डी0एफ0सी0।
34– श्रीमती अनुराधा दास गुप्ता, प्रोग्राम कोआर्डिनेटर, आई0एन0एस0आई0एस0टी0।
35– श्रीमती सुमन दास गुप्ता, इनोवेशन कोआर्डिनेटर, आई0एन0एस0आई0एस0टी0।
36– श्री अतुल भारवाहा, हेड व्यूजीनेस देव, आई0एम0एस0आई0ए0टी0।
37– श्रीमती सुनीता पटनायक, कारपोरेट अफेयर, वालमार्ट इण्डिया।
38– श्रीमती सुखमनी ग्रोवर, कारपोरेट अफेयर, वालमार्ट इण्डिया।

39– श्रीमती प्रावी कपूर,एसोसिएट प्रोग्राम देव, एन0एस0डी0सी0।
40– श्री संजीव कौरा, सी.ई.ओ., सी.एस.आर., टाइम्स ग्रुप।
41– श्री अभिषेक तिवारी, एम.डी. अभिटेक आईटी सिलोन।
42– श्री अमित श्रीवास्तव, सी.ई.ओ. अभिटेक आईटी सिलोन।
43– श्रीमती समीना बानो, चेयरपरसन, भारत अभ्युदया फाउन्डेशन।
44– श्रीमती ऐश्वर्या राय सिंह, आरएलएस सेवा, सौरव श्रीनेत, आरएलएस सेवा।
45– श्री देवेन्द्र गुप्ता, सी.ई.ओ. इकोजेन, साल्यूशन्स।
46– श्री जासिम खान, सीनि. मैनेजर, इरम साइन्टिफिक सिलोन।
47– श्री पंकज जैन, सी.ई.ओ. ज्ञानशाला।
48– श्री ब्यूमकेश मिश्रा, को–फाउन्डर, मेधा।
49– श्री क्रिशटोफर ट्यूरिलो, को–फाउन्डर, मेधा।
50– श्रीमती सनिता उपाध्याय, मेधा।
51– श्रीमती अनिता राना, जनहित फाउन्डेशन।
52– श्री अनिल सेंगर, प्रबन्धक, पंचायत उद्योग केन्द्र, महोबा।
53– श्री अपू थॉमस, हेड, एजूकेशन हेल्थ एण्ड इन्श्योरेन्स सर्विस, टाटा टेली सर्विस।
54– श्री जय मेंद्दीरत्ता, मैनेजर, एम. हेल्थ, टी.टी.एस.।
55– श्री संजय सिंह, परमार्थ।
56– श्री अशोक सिन्हा, परमार्थ।
57– श्री प्रशान्त, पी0ए0सी0एस0।
58– श्री राकेश सिंह, प्रदान।
59– श्री भूषन डेरे, सीईओ, लीव एण्ड बाउन्ड्स।
60– श्री प्रान्जित तालुकदार, आरएम स्पेशलिस्ट, विश फाउन्डेशन।
61– श्री केरनेल सुभाष देसवाल, सनशाइन फार्म्स।
62– श्री भास्कर त्रिपाठी, कापी एडिटर एण्ड रिपोर्टर, गेवान कनेक्शन रिपोर्टर।
63– श्री राकेश कुमार पाण्डे, सीईओ, श्रमिक भर्ती, राधा शुक्ला, श्रमिक भर्ती।